

जोहार छत्तीसगढ़

दैनिक हिन्दी

वर्ष: -14 अंक: 239 डाक पंजीयन 030/रायगढ़/2015-2017 मूल्य: 2 ₹ पृष्ठ: 4

जिला शिक्षा अधिकारी ने किया स्कूलों का आकस्मिक ...

धरमजयगढ़, शुक्रवार 8 जुलाई 2022

तुंहर विधायक, तुंहर द्वार अभियान का आगाज

पेज -4 पर

JOHAR CHHATTISGARH epaper for login www.joharchhattisgarh.in

एक नजर

36 ट्रेनें 16 जुलाई तक कैसिल



बिलासपुर। रेलवे बोर्ड ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ की 36 लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनों को बिना किसी वजह के कैसिल कर दिया है। 10 जुलाई से शुरू होने वाली ये गाड़ियां अब 16 जुलाई तक नहीं चलेंगी। लगातार ट्रेनों के कैसिल होने से यात्रियों की मुसीबत कम होने के बजाए बढ़ती जा रही है। इधर, रेलवे ने ट्रेनों के कैसिल करने पर यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद जताया है। रेलवे बोर्ड मार्च महीने से इन एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों को लगातार रद्द कर रहा है। पहले इन गाड़ियों को एक माह के लिए कैसिल किया गया था। फिर बाद में मई तक कैसिलेशन अवधि बढ़ा दी गई। जून में रेलवे बोर्ड ने अचानक आदेश जारी कर इन गाड़ियों को 9 जुलाई तक के लिए कैसिल किया था। इसके बाद अब फिर से एक सप्ताह के लिए ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 10 से 16 जुलाई तक बिलासपुर एवं भोपाल से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18236/18235 बिलासपुर-भोपाल-बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 9 से 15 जुलाई तक बिलासपुर से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18247 बिलासपुर-झुंझरीवा एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 को मिली कैबिनेट की मंजूरी

रायपुर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 का अनुमोदन किया गया। इस नीति से छत्तीसगढ़ के नागरिकों को बढ़ते पेट्रोल-डीजल के दाम से राहत मिलेगी वहीं पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भागीदारी सुनिश्चित होगी।

छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 में कमर्शियल एवं नॉन कमर्शियल दोनों प्रकार

के इलेक्ट्रिक वाहन के परिचालन को बढ़ावा देना शामिल है। इसके तहत राज्य में दो पहिया, तिपहिया, चार पहिया, माल वाहन, यात्री वाहन एवं अन्य श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदी पर विभिन्न छूट एवं सुविधाएं मिलेंगी। इस नीति के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों की आसान चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित किया जायेगा। ईवी मॉडलों को नेशनल और स्टेट हाइवे में निश्चित दूरी पर



मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट का अहम निर्णय

चार्जिंग प्वाइंट उपलब्ध होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 में पब्लिक चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये

सार्वजनिक और निजी ऑपरेटर्स को राज्य के सभी शहरों में नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे में चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित

करने के लिये आमंत्रित किया जायेगा। इन स्टेशनों की स्थापना के लिये न्यूनतम किराये पर भूमि प्रदान की जायेगी। चार्जिंग

स्टेशनों की स्थापना के लिये स्थानों की सूची राज्य ईवी

राज्यभर में ईवी चार्जिंग स्टेशनों का बिछाया जायेगा नेटवर्क

विकास निगम द्वारा तैयार की जायेगी। हाइवे पर स्थित पेट्रोल पंपों (रीफ्यूलिंग स्टेशन) को फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। नगर निगम फ्लाईओवर

पुलों के नीचे दो पहिया वाहनों के लिये मुफ्त या प्राथमिकता वाली पार्किंग के साथ चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान किया जायेगा। सरकारी कार्यालयों के पार्किंग क्षेत्रों में भी चार्जिंग प्वाइंट बनाये जाएंगे। चार्जिंग स्टेशनों के लिये लागू विद्युत शुल्क विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा। पुरानी गाड़ी में इलेक्ट्रिक किट लगाकर इलेक्ट्रिक वाहन में परिवर्तित करने पर भी प्रोत्साहन दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के कोयला कारोबारियों पर छापा

बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ और जांजगीर-चांपा की कोलवाशरी और कोल डिपो पहुंचे अफसर, स्टॉक में गड़बड़ी की जांच

रायपुर। छत्तीसगढ़ में चार विभागों की संयुक्त टीम ने कोयला कारोबार से जुड़ी कंपनियों के ठिकानों पर एक साथ दबिश दी है। बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा और जांजगीर-चांपा जिले की कोलवाशरी और कोल डिपो पर अफसरों का दल एक साथ पहुंचा। वहां कारोबार से जुड़े दस्तावेजों की जांच हो रही है।



अधिकारियों ने बताया, कोलवाशरी और कोल डिपो में कोयले के स्टॉक में गड़बड़ी सहित अन्य शिकायतें मिल रही थी। इनकी जांच के लिए खनिज, राजस्व, राज्य तस्ज और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम बनाई गई। इस

खनिज, राजस्व, राज्य GST और पुलिस के 50 अफसर शामिल

कोरबा के पावर प्लांट में भी छापा, अधिक कोल स्टॉक की शिकायत

पावर प्लांट में भी दबिश हुई

कोरबा जिले में पावर प्लांट चकाबूरा 2x135, 2x30, रतीजा पावर 50x2, मारुति 300 मेगावाट, रेकी पावर 63 मेगावाट में जांच टीम पहुंची। यहां अधिक मात्रा में कोल स्टॉक, पर्यावरण नियमों का उल्लंघन, भूमि संबंधी दस्तावेजों में कमियां, वेवब्रिज के कैलीब्रेशन में अंतर तथा अन्य कमियों की सघन जांच-पड़ताल की कार्रवाई की गई।

टीम में चारों विभागों के 50 अधिकारी शामिल किए गए। इन्हें 10 टीमों में बांटकर बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ एवं जांजगीर-चांपा जिलों में जांच शुरू की गई। संयुक्त टीम ने बुधवार को बिलासपुर जिले के गतौरा एवं हिंडाडीह स्थित हिन्द एनर्जी, हिन्द मल्टी, क्लीन कोल वाशरियों, गतौरा स्थित सत्या पावर कोलवाशरी, फील वाशरी, जांजगीर-चांपा जिले के बलौदा स्थित क्लीन कोल इंटरप्राइजेज, हिन्द एनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन, रायगढ़ जिले की कोल वाशरियों, कोल डिपो, कोरबा जिले में कोल वाशरी दीपका, गेवरा, चाकाबूरा, रैकी, रतीजा, मारुति, इंडस उद्योग एंड प्राइवेट लिमिटेड, कोठरी में दबिश दी।

कोयला स्टॉक में गड़बड़ी की जांच हो रही है

अधिकारियों ने बताया, कोल वाशरी और कोल डिपो में कोयला स्टॉक में गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं। इसके अलावा कर चोरी, राजस्व विवाद और पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के शिकायतों की जांच भी इस कार्रवाई का हिस्सा है। बताया जा रहा है कि दस्तावेजों और स्टॉक की जांच कुछ दिन तक जारी रहेगी।

इस बार छत्तीसगढ़ में औसत तुलना से 18 प्रतिशत कम हुई बारिश

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मौसम सूत्री बारिश ने 16 जून को दस्तक दे दी थी, जिसके बाद कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ ही कई जगहों पर तेज बारिश भी हुई है। प्रदेश के कई जिलों में अब भी औसत से कम बारिश दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ में औसत बारिश 258.3 मिलीमीटर होनी थी, लेकिन अब तक पूरे प्रदेश में 211.3 मिलीमीटर ही बारिश हो पाई है यह औसत बारिश की तुलना में 18% कम है। प्रदेश में औसत से अधिक बारिश 40% बीजापुर जिले में दर्ज की गई है। प्रदेश में औसत से कम बारिश 68% जशपुर जिले में दर्ज की गई है।

प्रदेश का मौसम पूर्वानुमान
मौसम वैज्ञानिक एचपी चंदा ने बताया 'एक ऊपरी हवा का चक्रवी चक्रवाती घेरा उत्तर ओडिशा के ऊपर स्थित है। मौसम द्रोणिका सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर स्थित है। जिसके प्रभाव से गुरुवार को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छोट पड़ने की संभावना है।

दंतेवाड़ा के बाल सुधार गृह से 9 बच्चे फरार

12 फीट ऊंची दीवार फांद कर भाग निकले, अब तक कोई सुराग नहीं

दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बाल सुधार गृह के 9 बच्चे फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बुधवार की देर रात सभी दीवार फांद कर भाग निकले। गुरुवार सुबह जब बाल सुधार गृह के अन्य बच्चे और गार्ड उठे और रोज की तरफ सभी की गिनती करवाई गई। उसमें 9 बच्चे कम मिले। सभी कमरों में तलाशी ली गई, लेकिन कहीं नहीं मिले। शुरुआती जांच में सभी के दीवार फांद कर भागने की जानकारी लगी। मामला दंतेवाड़ा सिटी कोतवाली क्षेत्र का है। DSP सोनिया ने बताया कि, सुबह 9 बच्चों के भागने की जानकारी



मिली। बाल सुधार गृह के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आसपास के थाना क्षेत्रों में सूचना दे दी गई है। इसके अलावा जवानों को मुस्तैद कर खोजबीन की जा रही है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। जांच के बाद ही सारी जानकारी देंगे। इधर सूत्रों के मुताबिक, फरार बच्चे इससे पहले भी भागने की कोशिश

कर चुके थे, लेकिन कामयाब नहीं हुए। सुरक्षा पर उठे सवाल
दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय में गायत्री मंदिर चौक से अस्पताल जाने वाली सड़क के किनारे ही बाल सुधार गृह है। इस पूरे कैम्प में चारों तरफ करीब 10 से 12 फीट की ऊंची दीवार हैं। अफसरों की माने तो यहां सुरक्षाकर्मी 24 घंटे ड्यूटी में तैनात रहते हैं। बुधवार की रात भी यदि सभी ड्यूटी कर रहे थे तो आखिर बच्चे भागे कैसे? अब यह सवाल खड़े हो रहा है।

ठेकेदार की मनमानी और प्रशासन की मौन स्वीकृति ठगे महसूस कर रहे आदिवासी किसान

जोहार छत्तीसगढ़-धरमजयगढ़।

ठेकेदार की मनमानी और प्रशासन की मौन स्वीकृति ठगे महसूस कर रहे हैं आदिवासी किसान। रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ से कापू रोड का एडीबी प्रोजेक्ट के तहत सड़क का निर्माण किया जा रहा है

जिसमें धरमजयगढ़ सहित 13 ग्रामों के किसानों का भूमि प्रभावित हो रहा है जिसके भूमि का अर्जन किया जाना है। पर यहां नियम कानून को जेब में रखने वाले ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा



क्षेत्र के भोले-भाले आदिवासियों को धमका चमका के भू-अर्जन किए बिना ही किसानों की जमीन पर कब्जा कर काम किया जा रहा है किसानों द्वारा विरोध करने पर ठेकेदार के गुंडे नूमा कर्मचारियों द्वारा धमकाया जाता है कि यह



शासकीय योजना है मुआवजा मांगना है तो एएसडीएम से मांगो। विदित हो पीछले दो वर्ष से किसानों की जमीन पर अवैध रूप से ठेकेदार द्वारा कब्जा कर रखा गया है जिससे किसानों को अपने खेतों में कृषि कार्य करने में दिक्कत आ

रहा है। यहां यह बताया जा रहा है कि यह अनुसूचित क्षेत्र है यहां किसी भी तरह के कार्यों के लिए ग्राम सभा से अनुमोदन जरूरी है लेकिन प्राप्त जानकारी अनुसार ठेकेदार द्वारा इसमें फर्जीबाड़ी किया जा रहा है सबसे आश्चर्य की बात है कि भू-अर्जन अधिकारी एसडीएम की इन सब फर्जी कार्यों में मौन स्वीकृति है। अगर इस परियोजना का उच्च स्तरीय जांच किया गया तो करोड़ों का घोटाला उजागर होगा साथ ही खनिज संपदा का अवैध दोहन का मामला भी सामने आ सकता है।

आर्थिक मदद.. राज्य सरकार गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 20 लाख रुपये तक दे रही सहायता

गंभीर बीमारी से लड़ रहे मरीजों के लिए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना बनी वरदान

रायपुर। गंभीर बीमारियों से पीड़ित जरूरतमंद मरीजों के लिए राज्य शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना वरदान साबित हो रही है।



इस योजना के तहत राज्य सरकार गंभीर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए 20 लाख रुपए तक आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इससे हजारों

जिंदगीयों को नया जीवन मिल रहा है, इनमें कोरबा शहर तुलसीनगर वार्ड में रहने वाली श्रीमती सीता देवी भी हैं। अल्टास्टिक एनीमिया

की गंभीर बीमारी से जूझ रही सीता देवी को योजना के तहत 15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी। राज्य सरकार से

मिली सहायता के फलस्वरूप सीता देवी का सफलतापूर्वक एलोपैथिक बोन मैरो प्रत्यारोपण किया गया। प्रत्यारोपण के बाद सीता देवी अब पूरी तरह से ठीक एवं स्वस्थ है। सीता देवी के पति श्री सुभाष कुमार ने शासन की इस जीवनदायनी योजना की प्रशंसा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना से उनकी पत्नी की जान बच पायी है। आठ वर्ष से बीमारी से जूझ रही पत्नी के इलाज में उनके बहुत पैसे खर्च हो गये थे, फिर भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी।

चिकित्सकों ने आखरी उम्मीद के रूप में बोन मैरो ट्रांसप्लान्ट करने की सलाह दी। इलाज में लगभग 15-20 लाख रुपये खर्च का अनुमान बताया गया। सुभाष कुमार ने बताया कि गंभीर अवस्था में पहुंच चुकी पत्नी के इलाज के लिए मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना से फिर से आशा बंधी। राज्य सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए उनके आवेदन पर हफ्ते भर में ही इलाज के लिए 15 लाख रुपये की स्वीकृति दे दी गई। जिसके फलस्वरूप सफलतापूर्वक जल्द ही उनकी पत्नी का बोन मैरो का ट्रांसप्लान्ट हो पाया।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में शनिवार मलब बगलेस-डे हो गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके व्यापक निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक अब सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को बच्चों को बस्ता लेकर स्कूल नहीं जाना होगा। स्कूल में उनका पूरा दिन योग, पीटी, खेलकूद, संगीत-नाटक-कहानी और ऐसी ही अन्य गतिविधियों में बीतेगा। अधिकारियों का कहना है, स्कूली शिक्षा को रोचक, व्यावहारिक और अपने आस-पास के माहौल से जोड़ने के लिए यह कोशिश शुरू की जा रही है। जिला शिक्षा

अधिकारियों से कहा गया है कि बगलेस-डे के दिन स्कूलों में अलग-अलग समय निर्धारित कर योग-व्यायाम, एक दूसरे से सीखना, समूह अधिगम, खेल और पुस्तकालय, समूह कार्यक्रम, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधि होंगी। कक्षा पहली से 8वीं तक के स्कूलों में व्यायाम, योग, क्रीड़ा प्रतियोगिता, साहित्यिक-सांस्कृतिक गतिविधियां, मूल्य-शिक्षा, कला-शिक्षा, पुस्तकों के अतिरिक्त पुस्तकालय एवं अन्य पठन सामग्रियों का उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है।

अनुशासित जीवन का मार्ग है अग्निपथ, शिक्षा पर जोर देने की जरूरत

सशस्त्र बलों को हमारे देश में सबसे विश्वसनीय, ईमानदार और अनुशासित संगठन के रूप में आदर दिया जाता है। राष्ट्र के प्रति बद्धता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। लगभग दो दशक पहले मैंने मुंबई में एक अभिनेता मित्र के साथ एक फिल्म के सेट पर आधा दिन बिताया। वहां मुझे भारत के शीर्ष अभिनेताओं में से एक के साथ बातचीत का अवसर मिला।

हम हर तरह की बातें कर रहे थे और हमारी बातचीत राष्ट्रीय चरित्र पर होने लगी, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हर युवक या युवती को सैन्य जीवन का स्वाद चखना चाहिए, क्योंकि इससे राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होगा। सेना आपके व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करती है। हर किसी के लिए सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करना संभव नहीं था, क्योंकि यह एक महंगा प्रस्ताव था और एक विकासशील राष्ट्र के रूप में हम इसे वहन करने में सक्षम नहीं होंगे और हमने इसी निष्कर्ष के साथ उस पर बातचीत को विराम दिया। हममें से कुछ लोग कहते हैं कि हमारा कोई राष्ट्रीय चरित्र नहीं है और ऐसा कहने वाले पूरी तरह से गलत नहीं हैं। हमने मूल्यों और चरित्र को खिड़की से ऐसे बाहर फेंक दिया है, मानो कुछ हुआ ही नहीं। युवा बसें जला रहे हैं, मानो



अग्निवीर

अग्निवीर 18 से 21 साल की उम्र में सेना में शामिल हो जाएगा और चार साल बाद 22 से 25 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाएगा, जो एक नई पारी शुरू करने के लिए अच्छी उम्र है। फांज काफका ने कहा है, ईश्वर आपको बादाम देता है, वह उसे आपके लिए तोड़ता नहीं है।

कानून या बड़ों या सरकार की उन्हें कोई परवाह नहीं है। पत्थर फेंकना

और अजीबोगरीब कारणों से किसी को बर्बर हत्या करना दिमाग को चकरा देता है। खबरों में भी यही सब रहता है। स्कूल छात्रों को अनुशासित करने के लिए जुड़ रहे हैं, माता-पिता परेशान हैं, क्योंकि बच्चे उनकी सुनते नहीं और ज्यादातर माता-पिता स्कूली कर्मचारियों को इसमें सहायता भी नहीं करते! सबसे पहले सरकार को मूल्यों वाली शिक्षा पर जोर देना चाहिए। गणित और विज्ञान से भी ज्यादा इसे तकजो मिलनी चाहिए। देश में दस फीसदी कम इंजीनियर हों, तो चलेगा, लेकिन दस फीसदी बुरे चरित्र वाले लोगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्या कोई ऐसे व्यक्ति को चपरासी भी रखना चाहेगा, जिसका चरित्र ठीक नहीं हो या वह भरोसेमंद नहीं हो? कभी नहीं। माता-पिता या शिक्षकों के जरिये आप युवा पीढ़ी में मूल्यों की

समझ पैदा नहीं कर सकते। इसके लिए स्थायी समाधान ढूँढ़ने होंगे, भले ही वे कठोर हों। और यह काम रातोंरात नहीं हो सकता है। इसमें लंबा समय लगेगा। आज युवा अच्छे वेतन वाली, आरामदायक नौकरी चाहते हैं, जहां उन्हें कोई सवाल न पूछे और वह काम करे या नहीं, उसे पूरा सम्मान मिलना चाहिए। जबकि एक सैनिक बाहरी दुश्मनों से राष्ट्र की रक्षा करता है, ज्यादा वेतन भी नहीं लेता, और घर-परिवार से दूर दुर्गम जगहों में काम करता है। जाहिर है, दोनों में जो फर्क है, वह है चरित्र। यदि 1.3 अरब की आबादी में से थोड़े से लोगों को हम चरित्रवान बना सकें, तो यह एक बड़ी शुरुआत होगी। यदि हम सभी युवाओं को सेना की रक्षा करनी है, ज्यादा वेतन भी नहीं रख सकते, तो कुछ अच्छे पुरुष व महिलाओं को अग्निवीर के रूप में

चार साल के लिए रखें, तो यह अच्छी शुरुआत होगी। ये थोड़े से चरित्रवान लोग समाज को तस्वीर बदल सकते हैं। अग्निवीरों को सेवा के चौथे वर्ष में प्रति महीना 40,000 रुपये मिलेंगे। यानी प्रति वर्ष 4.8 लाख रुपये का पैकेज, जो मध्य स्तरीय बिजनेस स्कूल के एमबीए को भी नहीं मिलता। इससे भी बड़ी बात है कि सरकार के समान योगदान के बाद सेवा खत्म होने पर अग्निवीरों को 11.771 लाख रुपये मिलेंगे, जो कर मुक्त है। यह बताना भी ठीक होगा कि रहने, खाने, चिकित्सा आदि रोजमर्रा की अधिकांश जरूरतों के लिए सेना खुद खर्च करेगी, इसलिए अग्निवीरों को इन सब पर खर्च करने की जरूरत नहीं है। कॉरपोरेट भाषा में कंपनी की सालाना सीटीसी 4.8 लाख रुपये से बहुत ज्यादा होगी। इसलिए बारहवीं पास के लिए छह लाख

का पैकेज बहुत बड़ी बात है। मान लीजिए, वही व्यक्ति अग्निवीर बनने के बजाय बारहवीं के बाद कॉलेज में स्नातक करने जाता है। पैसे खर्च करने और तीन साल कॉलेज में बिताने के बाद भी नौकरी की गारंटी कहाँ है? तीन साल बाद उसके पास न नौकरी होगी, न पैसे होंगे और न ही हुनर होगा। वह न अपने माता-पिता की मदद कर सकता है, न राष्ट्र या समाज की। दुनिया भर में निजी क्षेत्रों में नौकरी पर रखने से ज्यादा तेजी से नौकरी से निकाला जाता है। बीस हजार रुपये प्रति महीने की नौकरी के लिए कई चरणों में इंटरव्यू होते हैं, लेकिन मिनटों में बिना किसी इंटरव्यू के उसे हटा दिया जाता है। इसलिए युवाओं को सरकार को दोष देने के बजाय नौकरी के लायक खुद को तैयार करना चाहिए।

वीरेंद्र कपूर

संपादकीय

चीन का अविश्वास

चीन ने पाकिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों की रक्षा का भार किसी चीनी एजेंसी को देने की मंशा जताई है। स्पष्टतः किसी अन्य देश को क्षमता पर अविश्वास करते हुए वहां अपनी परियोजनाओं को आगे बढ़ाना चीन की समस्याग्रस्त सोच है। बेहतर तो यह होता कि चीन इस प्रश्न पर विचार करता कि पाकिस्तान जैसे उसके दोस्त देश में उसकी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को लेकर विरोध भाव क्यों फैलता जा रहा है? चीन इन्हें सबके फायदे के प्रोजेक्ट बताता है। लेकिन जिन लोगों के कथित लाभ के लिए उन्हें निर्मित किया जा रहा है, आखिर वे उससे क्यों खफा हैं? लेकिन इस पर विचार करने के बजाय वह अब पाकिस्तान में अपने सुरक्षा बल तैनात करना चाहता है। फिलहाल, पाकिस्तान गहरे आर्थिक संकट में है। चीन और सऊदी अरब ही दो ऐसे देश हैं, जो इस मौके पर उसकी मदद के लिए सामने आए हैं। इसलिए पाकिस्तान चीनी मंशा को कब तक ठुकरा पाएगा, कहना मुश्किल है। लेकिन किसी अन्य देश की क्षमता पर अविश्वास करते हुए वहां अपनी परियोजनाओं को आगे बढ़ाना चीन की एक समस्याग्रस्त मानसिकता है। एक वेबसाइट की एक खास रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों की रक्षा का भार किसी चीनी एजेंसी को देने की मंशा जताई है। गौरतलब है कि हाल में पाकिस्तान में कई चीन की परियोजना वाले कई ठिकानों पर हमले हुए हैं। उनमें चीनी नागरिकों की मौत भी हुई है। अभी आई खबर के मुताबिक चीन के अनुरोध को फिलहाल पाकिस्तान सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। लेकिन चीन ने इस मुद्दे पर पाकिस्तान सरकार पर दबाव बना रखा है।

पिछले दरवाजे से जीएम फसल लाने की तैयारी, नए सिरे से फिर उठते विवाद के मायने

हाल के समय में भारत सहित अनेक देशों में नए सिरे से विवाद आरंभ हो गया है कि जीन एडिटिंग तकनीक के माध्यम से पिछले दरवाजे से जीएम (जेनेटिकली मोडिफाइड या जेनेटिक रूप से संशोधित) फसलों को प्रवेश दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। यूरोपीय संघ में अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि जीन एडिटिंग की तकनीक को भी जीएम फसलों की श्रेणी में ही रखा जाएगा। इसके बाद जीएम फसलों के प्रसार वाली कंपनियों का ध्यान भारत की ओर गया है, इस कारण हमारे देश में जीएम खाद्य फसलों व खाद्यों के प्रसार की आशंका बढ़ गई है।

ध्यान रहे कि अभी तक केवल कपास की गैर-खाद्य फसल के मामले में ही जीएम फसल बीटी कॉटन की अनुमति दी गई थी। किसी जीएम खाद्य फसल की अनुमति नहीं दी गई है। दो बार जीएम बैंगन की फसल व फिर जीएम सरसों को फैलाने के लिए बहुत जोर लगाया गया, पर व्यापक विरोध के कारण यह प्रवेश नहीं मिल सका। जीएम फसलों के विरोध का एक मुख्य आधार यह रहा है कि ये फसलें स्वास्थ्य व पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित नहीं हैं तथा यह अस्स जेनेटिक प्रदूषण के माध्यम से अन्य सामान्य फसलों व पौधों में फैल सकता है। इस विचार को ईडिपेंडेंट साइंस पैनल (स्वतंत्र विज्ञान मंच) ने बहुत सारगर्भित ढंग से व्यक्त किया है। इस पैनल में एकत्र हुए विश्व के अनेक देशों के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों व विशेषज्ञों ने जीएम फसलों पर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किया, जिसके निष्कर्ष में उन्होंने



कृषि व खाद्य क्षेत्र में जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रौद्योगिकी मात्र लगभग छह-सात बहुराष्ट्रीय कंपनियों (व उनकी सहयोगी या उप-कंपनियों) के हाथ में केंद्रित हैं। इन कंपनियों का मूल आधार पश्चिमी देशों व विशेषकर अमेरिका में है।

कहा है - 90% जीएम फसलों के बारे में जिन लाभों का वादा किया गया था, वे प्राप्त नहीं हुए हैं और ये फसलें खेतों में बढ़ती समस्याएं उत्पन्न कर रही हैं। अब इस बारे में व्यापक सहमति है कि इन फसलों का प्रसार होने पर ट्रांसजेनिक प्रदूषण से बचा नहीं जा सकता है। इन फसलों की सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएं उत्पन्न होती हैं। यदि इनकी उपेक्षा की गई, तो स्वास्थ्य व पर्यावरण की क्षति होगी जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है, जिसे फिर ठीक नहीं किया जा

सकता है। जीएम फसलों को अब दृढ़ता से खारिज कर देना चाहिए, अस्वीकृत कर देना चाहिए। 2009-10 में भारत में बीटी बैंगन के संदर्भ में जीएम के विवाद ने जोर पकड़ा, तो विरोध के 17 विख्यात वैज्ञानिकों ने भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस बारे में नवीनतम जानकारी उपलब्ध करवाई। पत्र में कहा गया कि जीएम प्रक्रिया से गुजरने वाले पौधे का जैव-रसायन बुरी तरह अस्त-व्यस्त हो जाता है, जिससे उसमें नए विषैले या एलर्जी उत्पन्न करने वाले तत्वों का प्रवेश हो सकता है। उसके पोषक गुण कम हो सकते हैं या बदल सकते हैं। जीव-जंतुओं को जीएम खाद्य खिलाते पर आधारित अनेक अध्ययनों से जीएम खाद्य के गुर्दे (किडनी), यकृत (लिवर) पेट व निकट के अंगों (गट), रक्त कोशिका, रक्त जैव रसायन व प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनोटी सिस्टम) पर नकारात्मक स्वास्थ्य

असर सामने आ चुके हैं। कृषि व खाद्य क्षेत्र में जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रौद्योगिकी मात्र लगभग छह-सात बहुराष्ट्रीय कंपनियों (व उनकी सहयोगी या उप-कंपनियों) के हाथ में केंद्रित हैं। इन कंपनियों का मूल आधार पश्चिमी देशों व विशेषकर अमेरिका में है। इनका उद्देश्य जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से विश्व कृषि व खाद्य व्यवस्था पर ऐसा नियंत्रण स्थापित करना है, जैसा विश्व इतिहास में आज तक संभव नहीं हुआ है। इन सब तथ्यों व जानकारियों को ध्यान में रखते हुए सभी जीएम फसलों का विरोध जरूरी है। कुछ समय पहले देश के महान वैज्ञानिक प्रोफेसर पुष्प भार्गव का निधन हुआ है। वह सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हैदराबाद के संस्थापक निदेशक रहे व नेशनल नॉलेज कमिशन के उपाध्यक्ष रहे।

भारत डोगरा

मिला जुला

अंधाधुंध गोलियां चलाकर भागे कातिल; भारी फोर्स तैनात

टीएमसी नेता समेत 3 लोगों की हत्या

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में टीएमसी नेता स्वपन माझी की आज सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके साथ ही दो अन्य लोगों को गोली मारी गई, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई।

यह तिहरा हत्याकांड आज सुबह उस वक हुआ, जब टीएमसी नेता

बाइक से अपने दो साथियों के साथ घर से निकले थे। इस दौरान कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल को रोककर अंधाधुंध फायरिंग की और फरार हो गए। गोलियां लगने से टीएमसी लीडर और उनके दोनों साथियों को मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल भारी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया। मौके से कारतूस के खोखे और बम बरामद किए जाने की खबर है। स्वपन माझी टीएमसी के नेता हैं और स्थानीय पंचायत के सदस्य थे। केनिंग पश्चिम के टीएमसी विधायक परेश राम दास ने कहा कि हत्यारों ने पहले तो टीएमसी नेता समेत तीन लोगों को गोली मारी और फिर उनके सिर भी काटने की कोशिश की थी। एक



वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, 'तीन लोगों की हत्या हुई है। जांच जारी है। मृतकों की पहचान स्वपन माझी, ज्ञानतु हलदर और भूतनाथ प्रमाणिक के तौर पर हुई है।' यह घटना आज सुबह करीब 9 बजे हुई, जब तीनों टीएमसी के

पहले ही जताई थी हत्या की आशंका, विधायक ने किया खुलासा

केनिंग की गोपालपुर पंचायत के वह सदस्य थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक अज्ञात लोगों ने मोटरसाइकिल को रोकना था, जिसमें स्वपन माझी समेत तीनों लोग सवार थे। पहले उन लोगों ने माझी को गोली मारी और फिर जब हलदर और प्रमाणिक ने भागने की कोशिश की तो उन्हें भी गोली मार दी गई। उन लोगों की हत्या करने के बाद उनका गला भी काटने की कोशिश की गई थी। विधायक परेश राम दास ने कहा, 'माझी मंगलवार रात को मेरे पास आए थे और कहा था कि मेरी हत्या की जा सकती है। मैंने उनसे कहा था कि गुरुवार दोपहर को आए ताकि मैं पुलिस से बात करूँ और सुरक्षा की कुछ व्यवस्था कराई जा सके।'

इस घटना के लिए टीएमसी ने एक तरफ भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है तो वहीं भाजपा का कहना है कि यह उसकी आंतरिक कलह का नतीजा है। टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, 'हम इस मामले में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। यह टीएमसी पर हमला है। भाजपा हमारे दल को कमजोर करना चाहती है और राज्य की छवि को भी खराब करने का प्रयास कर रही है। वे हिंसा कर रहे हैं और फिर शिकायतें करते हैं कि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है।' इस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि टीएमसी की इस थ्योरी पर तो कोई बच्चा भी भरोसा नहीं करेगा।

लालू को देखने दिल्ली एम्स पहुंचे केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय



पटना। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती करा दिया गया है। पटना में पत्नी राबड़ी देवी के सरकारी आवास में गिरने के कारण कंधे में फ्रैक्चर व चोट के बाद तबीयत बिगड़ने पर उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बीती रात वहां से एयर एंबुलेंस द्वारा दिल्ली ले जाकर उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। इस बीच तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि दवाओं के ओवरडोज के कारण लालू की हालत बिगड़ी। उनका पूरा शरीर लाक हो चुका है। आज दिल्ली एम्स में भर्ती लालू को देखने के केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय पहुंचे। उन्होंने डाक्टरों से मिलकर लालू के स्वास्थ्य का हाल भी जाना।

छ.ग. मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 का उल्लंघन, 3 राईस मिलों पर शिकंजा

81 हजार 6 सौ 14 क्विंटल धान और 6 हजार 445 क्विंटल चावल जब्त

जोहार छत्तीसगढ़- महासमुंद।

खाद्य विभाग द्वारा नियमों की अनदेखी करने वाले जिले के राईस मिलों के खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य अधिकारी ने बताया कि मेसर्स मनीष एण्ड एसोसिएट्स राईस मिल, ग्राम मौलीमुड़ा, तहसील बागबाहरा एवं मेसर्स बालाजी इण्डस्ट्रीज एण्ड ग्राम झलप, तहसील बागबाहरा का औचक निरीक्षण किया गया। जिसमें मेसर्स मनीष एण्ड एसोसिएट्स राईस मिल द्वारा कस्टम मिलिंग से संबंधित पंजियों संधारित नहीं किये जाने के कारण खाद्य विभाग में सत्यापित प्रति खाद्य विभाग में जमा नहीं किये जाने के कारण खाद्य विभाग ने फर्म द्वारा छत्तीसगढ़ मिलिंग चावल उपार्जन आदेश, 2016 के प्रावधानों का किराया जाना पाया गया तथा फर्म के पार्टनर मनीष अग्रवाल से 52814 क्विंटल धान और 2984 क्विंटल चावल जब्त किया गया है। इसी प्रकार मेसर्स बालाजी इण्डस्ट्रीज द्वारा भी कस्टम मिलिंग से संबंधित पंजियों संधारित नहीं किये जाने तथा मिलर माइयूल में मिलिंग संबंधी मासिक जानकारी दर्ज कर मासिक विवरणी को सत्यापित प्रति खाद्य विभाग में जमा नहीं किये जाने के कारण खाद्य विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश

2016 के अंतर्गत प्रकरण निर्मित कर फर्म के संचालक मनोज कुमार जिनंद से धान 28800 क्विंटल एवं चावल 3461 क्विंटल जब्त किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम कार्रवाई की जा रही है। वहीं खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में कस्टम मिलिंग करने के लिये धान का उठाव पश्चात् चावल जमा नहीं करने के कारण खाद्य विभाग के द्वारा पिछले वर्ष इसी माह की तारीख 6 जुलाई 2021 को मेसर्स लक्ष्मी राईस मिल बसना को जांच की गई थी। जांच में छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश, 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर 4400 क्विंटल धान,

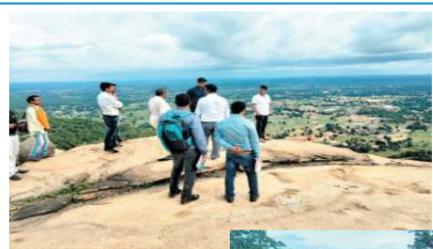
938 क्विंटल उसना चावल एवं 108.50 क्विंटल कनकी जब्त कर प्रकरण निर्मित किया गया था। प्रकरण में विभाग के द्वारा फर्म के संचालक राजेश अग्रवाल को कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिवस के अंदर लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया। फर्म के द्वारा समयावधि में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये जाने पर फर्म के मिल परिसर को विद्युत आपूर्ति विच्छेद कर दी गई है तथा कृषि उपज मण्डी समिति, बसना के द्वारा फर्म के नाम से जारी अनुज्ञापि निलम्बित करने की कार्रवाई की जा रही है।

कलेक्टर ने जशपुर के पर्यटन स्थल देशदेखा का किया आकस्मिक निरीक्षण

पर्यटन स्थल की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे- कलेक्टर

जोहार छत्तीसगढ़- जशपुर।

कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने विगत दिवस जशपुर जनपद के किनकेल पंचायत स्थित देशदेखा पर्यटन स्थल का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जितेंद्र यादव, पुलिस अधीक्षक जशपुर राजेश अग्रवाल, जनपद सीईओ प्रेम सिंह मरकाम सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने देशदेखा पर्यटन स्थल स्वच्छता बनाए रखने पर विशेष ध्यान देने की बात कही। इस हेतु स्थल की नियमित साफ सफाई



करने के निर्देश दिए। उन्होंने वहां आने वाले पर्यटकों की सुविधाओं के लिए खाली जगह पर बैठक सहित अन्य आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा। अग्रवाल ने उक्त स्थल पर दुर्घटना से बचाव के लिए स्थल के किनारे-किनारे स्थानीय साधनों से

धेरा करने एवं असाधारण तत्वों का भी पर्यटन स्थल पर रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने ने पर्यटन स्थल पर निर्माणधीन शौचालय का भी अवलोकन कर शौचालय निर्माण के शेष कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने एवं गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

धेरा करने एवं असाधारण तत्वों का भी पर्यटन स्थल पर रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने ने पर्यटन स्थल पर निर्माणधीन शौचालय का भी अवलोकन कर शौचालय निर्माण के शेष कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने एवं गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

जिला शिक्षा अधिकारी ने किया स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण

जोहार छत्तीसगढ़-
बेमेतरा।

जिला शिक्षा अधिकारी अरविन्द कुमार मिश्रा द्वारा कल विकासखण्ड नवागढ़ के शासकीय प्राथमिक शाला जैतपुरी तथा सम्बलपुर, हाई स्कूल खेड़ा, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मूरता तथा अधियारखोर, नवाजतन प्रशिक्षण केन्द्र सम्बलपुर एवं अधियारखोर के साथ ही विकासखण्ड बेरला के शासकीय प्राथमिक शाला खर्रा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान शासकीय



प्राथमिक शाला जैतपुरी निर्धारित विद्यालयीन समय पर बंद पाया गया, बच्चे विद्यालय परिसर के अन्दर तथा मुख्य सड़क पर खेलते पाए गए। जिला शिक्षा अधिकारी मिश्रा ने बच्चों से विद्यालय के शिक्षकों की उपस्थिति तथा पढ़ाई के संबंध में बात की। बच्चों से पूछे जाने पर विद्यालय में रूपेन्द्र

कुमार साहू, अनुप कुमार वर्मा एवं कौशल कुमार गेन्डे कार्यरत होने की जानकारी दी गई। बच्चों ने बताया कि इनमें से शिक्षक साहू एवं वर्मा द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाता है, शिक्षक गेन्डे कभी-कभी विद्यालय में उपस्थित होते हैं तथा विलम्ब से आते हैं और अध्यापन कार्य भी नहीं

कराया जाता। 16 मार्च 2022 को भी विद्यालय के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान कौशल कुमार गेन्डे विद्यालय में अनुपस्थित पाए गए थे जिसके लिए संबंधित शिक्षक को नोटिस जारी किया गया था परन्तु संबंधित द्वारा अनुशासनहीनता दिखाते हुए आज पर्यन्त जवाब प्रस्तुत नहीं किया

गया है। संबंधित द्वारा लगातार विद्यालयीन कार्य में स्वेच्छाचारिता तथा कार्यालयीन आदेशों की अवहेलना की गई है इस पर जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा द्वारा संबंधित शिक्षक कौशल कुमार गेन्डे को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है। नवाजतन प्रशिक्षण संकुल केन्द्र सम्बलपुर में आयोजक 3 सीएसी तथा समस्त प्रशिक्षणार्थी शिक्षक निर्धारित समय प्रातः 10 बजे अनुपस्थित थे साथ ही नवा जतन प्रशिक्षण संकुल केन्द्र अधियारखोर में भी दोपहर 12 बजे तक प्रशिक्षणार्थियों के उपस्थिति अनुपस्थिति के संबंध में पंजी संधारित नहीं की गई थी। प्रशिक्षण केन्द्र में अनुशासनहीनता तथा शिक्षकों की समय में अनुपस्थिति के संबंध में प्रभारी एवं शिक्षकों को नोटिस जारी करने हेतु विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी नवागढ़ को निर्देशित किया गया है तथा समस्त प्रशिक्षणार्थियों के एक दिन का वेतन रोके जाने का निर्देश दिया गया। शासकीय हाई स्कूल

खेड़ा में प्रातः 10.45 बजे उपस्थित समस्त शिक्षक स्टाफ रूम में बैठे पाए गए, आज पर्यन्त शाला समय सारणी तैयार नहीं किया गया है। निरीक्षण के दौरान प्रायोगिक कक्ष बंद पाया गया। किसी भी विषय का प्रायोगिक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है तथा समस्त विषयों की पढ़ाई भी संतोषजनक नहीं पाई गई। जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा ने संबंधित आहरण संचितरण अधिकारी को उपस्थित समस्त शिक्षकों का एक दिन का वेतन रोके जाने हेतु निर्देशित किया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अधियारखोर तथा मूरता में भौतिक, रसायन, जीवविज्ञान विषय का प्रायोगिक कार्य प्रारंभ नहीं कराये जाने के संबंध में प्रभारी प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। विकासखंड बेरला के शासकीय प्राथमिक शाला खर्रा के शिक्षक मुकेश देवानं विना किसी सूचना में निर्धारित शाला समय में अनुपस्थित पाये गये। संबंधित देवानं को नोटिस जारी किया गया।

एक नजर

7 लीटर अवैध कच्ची महुआ

शराब एक गिरफ्तार

जोहार छत्तीसगढ़-रतनपुर।



कोटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम करपिहा में आरोपी राजकुमार मरावी अपने घर के पास आंगन में अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री करने के लिए रखा हुआ था आरोपी राजकुमार मरावी पिता स्वर्ण देवीलाल मरावी उम्र 43 वर्ष ग्राम करपिहा निवासी के कच्चे से कोटा पुलिस के द्वारा हाथ भट्टी से बना हुआ 7 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब जप्त कर आरोपी के खिलाफ अबकारी एक्ट अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया।

प्राकृतिक आपदा में जनहानि के दो मामलों में प्रभावित परिजन हेतु 8 लाख की राशि स्वीकृत

जोहार छत्तीसगढ़-जशपुर।

कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने प्राकृतिक आपदा में जनहानि के दो मामलों में प्रभावित परिजन हेतु आर.बी.सी. 6-4 के तहत 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। जिसमें संपर्क से पथलगांव तहसील के ग्राम बटुराकछार निवासी सोहदी बाई की मृत्यु 29 अगस्त 2021 को हो जाने पर मृतिका के निकटतम वारिस मृतिका के पति श्री पंडित राम हेतु 4 लाख एवं पथलगांव तहसील के ग्राम पंडरीपानी निवासी दया राम की मृत्यु 13 अगस्त 2021 को हो जाने पर मृतक के निकटतम वारिस मृतक की पत्नी श्रीमती फूलकुवारी हेतु 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

जिले में 1 जून से अब तक 128.6 मिमी वर्षा

जोहार छत्तीसगढ़-जशपुर।

जशपुर जिले में 1 जून से अब तक 128.6 मिमी औसत वर्षा हो चुकी है। जिले में बीते 10 वर्षों की तुलना में 7 जुलाई तक औसत वर्षा 265.7 मिमी हुई है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जून से अब तक जशपुर तहसील में 103.5 मिमी, मनोरा में 160.8 मिमी, कुनकुरी में 111.1 मिमी, दुलदुला में 155.2 मिमी, परसाबहार में 117.8 मिमी, बगीचा में 187.6 मिमी, कांसाबेल में 35.3 मिमी, पथलगांव में 110.5 मिमी एवं सजा में 175.6 मिमी वर्षा हो चुकी है। सर्वाधिक वर्षा बगीचा तहसील में दर्ज की गई है।

संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में आज जाति प्रमाण के संबंध में समाज प्रमुखों की बैठक

जोहार छत्तीसगढ़-जशपुर।

जिले में संभागीय आयुक्त जी.आर. चुरेन्द्र की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति समुदाय प्रमुखों की बैठक 8 जुलाई 2022 को अपराह्न 3.30 बजे कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित की गई है। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि बैठक में ऐसे जाति के समाज प्रमुख जिनके जाति प्रमाण पत्र बनाने में समस्या हो रही है वे निर्धारित तिथि को बैठक में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

कलेक्टर के संज्ञान के बाद अब बदलेगी सांगरपुर खुर्द की स्कूल की तस्वीर

कवर्था। जिले के नवपदस्थ कलेक्टर जनमेजय महोदय के संज्ञान के बाद कवर्था विकासखण्ड के प्राथमिक स्कूल सांगरपुर खुर्द की तस्वीर अब जल्द ही बदलेगी। कलेक्टर ने बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए संसाधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से जिला मिशन समन्वय को स्कूल में एक अतिरिक्त कक्षा निर्माण और मंच के पास एक शेड निर्माण की स्वीकृति करने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर के निर्देश पर नया भवन का प्रस्ताव संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय को भेजा गया है। साथ ही जिला शिक्षा मद से 40 हजार रुपए एवं जनप्रतिनिधि व अधिकारियों की मदद से 20 हजार एकत्र कर स्कूल में अन्य आवश्यक मरम्मत कार्य कराने का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि सांगरपुर खुर्द स्कूल परिसर के मंच में तिरपाल से लगाकर बच्चों की पढ़ाई करने वाली खबर सामने आई थी। कलेक्टर ने इस खबर को शीघ्रता से संज्ञान में लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने हाथीसार गांव में ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी

ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ लेने किया प्रोत्साहित

जोहार छत्तीसगढ़-
जशपुर।

कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने विगत दिवस जशपुर ब्लॉक के ग्राम हाथीसार पहुंचकर ग्रामीणों को विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी देते हुए उनकी समस्याओं के संबंध में चर्चा की। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव, एसपी राजेश अग्रवाल सहित अन्य अधिकारिगण उपस्थित थे।



पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता के साथ ही गाँव में स्कूल, आंगनवाड़ी के संचालन के संबंध में जानकारी लेकर स्थानीय अधिकारियों को गंभीरता से ग्रामीणों की समस्याओं

का निराकरण करने हेतु निर्देशित किया। कलेक्टर ने ग्रामीणों से आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, वन अधिकार पत्रा निर्माण के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि अभियान चलाकर शिविर के माध्यम से पात्र सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड, जाति एवं वन अधिकार पत्र बनाया जा रहा है। इस हेतु सभी पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। आप सभी योजना का लाभ लेने हेतु अपने स्थानीय अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं। उन्होंने इस दौरान ग्राम में बनाए गए स्टॉप डेम का भी मुआयना किया एवं डेम के साफसफाई के निर्देश अधिकारियों को दिए।

जोहार छत्तीसगढ़-
बेमेतरा।

जिला बेमेतरा में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना अंतर्गत जिले के चिन्हाकित हाट बाजारों में जाकर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे गैर संचारी रोग, डेंगू, टीबी, कुष्ठ रोग, एचआईवी जांच, मलेरियाए गर्भावस्था की जांच एनिमिया की जांच कर आवश्यकतानुसार दवाइयों का वितरण किया जाता है, साथ ही गंभीर पीड़ित मरीजों को उपचार के लिए उच्च स्तरीय स्वास्थ्य संस्थाओं में रेफर किया जाता है। जिससे मरीजों का समय रहते इलाज मुहैया कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक



का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र जहाँ स्वास्थ्य संस्था दूर है, उस स्थान पर लागने वाले हाट बाजारों में जाकर जन समुदाय को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना है, जिले में गठित टीम में 5 एमबीबीएस डॉक्टर की नियुक्ति की गई है, जिसमें से विकासखण्ड बेरला में

डॉ गरिमा वर्मा, विकासखण्ड बेमेतरा में डॉ मिलनदीप कौर, विकासखण्ड नवागढ़ में डॉ अंगेश्वर निषाद, विकासखण्ड साजा में डॉअमरेश शेष एवं आशिष खड्ग द्वारा जिले के विकासखण्डों में टीम लीडर के रूप में अपनी सेवाएँ प्रदान करेंगे।

नगरपालिका जशपुर में आज बनाया जाएगा आयुष्मान कार्ड

पात्र हितग्राहियों को आवश्यक दस्तावेज के साथ उपस्थित होने किया गया है अपील

जोहार छत्तीसगढ़-जशपुर।

कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल के निर्देशन में आज पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 5 बजे तक नगर पालिका जशपुर में आयुष्मान कार्ड पंजीयन का मेगा कैम्प लगाया जावेगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने बताया कि आयुष्मान कार्ड पंजीयन हेतु छूटे हितग्राहियों द्वारा राशनकार्ड, आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर के साथ सभी सदस्यों को उपस्थित होने कहा गया है। उन्होंने बताया कि नगरीय क्षेत्र के विभिन्न चार्डों में डोर-टू-डोर सर्वे के लिए विभिन्न अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिनके द्वारा शत प्रतिशत लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु हितग्राहियों के घर-घर जाकर, आयुष्मान कार्ड के पंजीयन हेतु नगरपालिका कार्यालय में उपस्थित होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिससे कोई भी हितग्राही योजना से वंचित न हो सके।



मोदी राज में महंगाई निरंकुश-रश्मि चंद्राकर

गरीब ही नहीं मध्यम वर्ग भी परेशान

जोहार छत्तीसगढ़-
महासमुंद।

कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉ रश्मि चंद्राकर ने बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा के मोदी सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि सरकार के पास कीमतें बढ़ने के हर तर्क मौजूद हैं, मगर उन्हें रोकने का एक भी उपाय नहीं है। महंगाई ने गरीब आदमी तो क्या, मध्यवर्ग के आदमी तक का जीना मुहाल कर दिया है, मगर सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। महंगाई खान की तरह लोगों के पीछे पड़ कर उनका जीना मुश्किल कर रही है। कभी खाद्य सामग्री, कभी पेट्रोल तो कभी एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं। इससे सिर्फ गरीब ही नहीं मध्यवर्ग के लोग भी परेशान होने लगे हैं। एलपीजी गैस डीलरों के



मुताबिक एप्रैल 2020 में एलपीजी का जो घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 596 रुपये में मिलता था। अब बढ़कर 1119 रुपये का हो गया है। पिछले दो वर्षों में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 523 रुपये बढ़ गए। इससे पिछले दो वर्षों में रसोई गैस सिलेंडर के दाम दोगुने बढ़ चुके हैं। मई से दिसंबर 2020 में एलपीजी के घरेलू सिलेंडर में कुल मिला कर 64 रुपये का इजाफा हुआ। जबकि वर्ष 2021 में अप्रैल माह में एकमुश्त 91 बढ़े। कुल

का इजाफा होता था, मगर अब हर दूसरे माह सिलेंडरों की कीमत में भारी वृद्धि की जा रही है। सरकार को आम लोगों का भी खयाल रखना चाहिए। एक ओर महंगाई से जनता परेशान है वहीं दूसरी ओर केंद्र के मोदी सरकार के द्वारा इन दिनों किसान विरोधी भाजपा सरकार जो छत्तीसगढ़ किसानों के लिए रासायनिक खाद नहीं भेज रही है जिसके कारण किसान यूरिया की दिक्रत से जूझ रहे हैं महासमुंद लोकसभा सांसद चुन्नी लाल साहू अपने आपको किसान बताते हैं और आज किसान डीएपी खाद की दिक्रत से जूझ रहे जिस पर सांसद चुन्नी साधे हुए बैठे हैं। उनकी चुन्नी ही भाजपा को किसान विरोधी चरित्र को दर्शाती है।

मिला कर अप्रैल से लेकर अक्टूबर 2021 के बीच घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में 306 की वृद्धि हुई। वृद्धि का यह दौर वर्ष 2022 में भी जारी है। वर्ष 2022 में मार्च माह में एक साथ पचास रुपये दाम बढ़े। मार्च से लेकर 6 जुलाई माह तक चार बार बढ़े दामों की वजह से एलपीजी रसोई गैस सिलेंडरों में 153 रुपये का इजाफा हो गया है। सरकार आम जनता को मानने पर तुली है। पहले कभी कभार सिलेंडर की कीमत में चंद रुपये

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत किसान फसलों का बीमा करा योजना का ले सकते लाभ

जोहार छत्तीसगढ़-
जशपुर।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ वर्ष 2022 अंतर्गत किसान प्राकृतिक आपदाओं, कीटों के प्रकोप से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति अपनी फसलों का बीमा कराकर योजना के माध्यम से ले सकते हैं।



किसानों से योजना का लाभ लेने हेतु अपील की है। उन्होंने बताया कि जिले में खरीफ मौसम वर्ष 2022 में धान सिंचित, धान अर्धसिंचित, मक्का, उड़द, अरहर, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन फसलें अधिसूचित हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के ऋणी एवं अऋणी किसान नवीनतम आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि व फसल बुवाई संबंधित आवश्यक दस्तावेज सहित पंजीकरण कराने हेतु अपने नजदीकी बैंक शाखा,

सहकारी सोसायटी, लोक सेवा केंद्र, पोस्ट ऑफिस से संपर्क कर फसल का बीमा करावा सकते हैं। कृषक द्वारा देय प्रीमियम बीमित राशि का 2 प्रतिशत है तथा शेष प्रीमियम राशि का भुगतान भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलभराव, बादल फटने, आकाशीय बिजली से नुकसान होने पर स्थानीय आपदा, फसल कटाई उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में

सुखाई हेतु रबी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम चक्रवाती वर्षा से नुकसान होने पर या कर्म वर्षा या विपरीत मौसम परिस्थितियों के कारण फसल न बोए जाने पर एवं फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त उपज आंकड़े, निर्धारित थ्रेशहोल्ड उपज से कम आने पर दावा भुगतान किया जाएगा। साथ ही अनवारी के आंकड़े इस योजना अंतर्गत दावा भुगतान के लिए मान्य नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि यह योजना ऋणी किसानों के लिए विकल्प चयन आधार पर क्रियान्वित होगी एवं ऋणी किसान जो उक्त योजना में शामिल नहीं होना चाहते, उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी चयन प्रपत्रानुसार हस्ताक्षर सहित घोषण पत्र बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के 07 दिन पूर्व तक संबंधित वितीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा।

नेशनल लोक अदालत में राजस्व प्रकरण के निराकरण के संबंध में कलेक्टर से की गई चर्चा

जोहार छत्तीसगढ़-
बेमेतरा।

आगामी नेशनल लोक अदालत 13 अगस्त 2022 के सफ ल आयोजन के संबंध में अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयदीप विजय निमोणकर ने जिला न्यायाधीश कक्ष में बेमेतरा कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक बेमेतरा धर्मेन्द्र छवई सहित न्यायाधीशगण की बैठक ली। बैठक जिला न्यायाधीश के विश्राम कक्ष में आयोजित कर न्यायाधीशगण को अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों में मध्य प्री-सिटिंग कराकर आपसी सुलह समझौते से प्रकरणों को निराकरण करने प्रोत्साहित किया एवं पूर्व में चिन्हाकित राजीनामा योग्य प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य और राजीनामा योग्य प्रकरणों में अधिक अधिक से पक्षकारों के साथ प्री सिटिंग



करने हेतु चर्चा की गई। अध्यक्ष जयदीप निमोणकर द्वारा राजस्व न्यायालय में लंबित प्रकरणों को लोक अदालत में निराकृत किये जाने हेतु कलेक्टर बेमेतरा से चर्चा की गई। राजस्व न्यायालयों में लंबित खतेदारों के मध्य आपसी बटवारे के मामले, वारिसों के मध्य बटवारे के मामले, याददास्त के आधार पर बटवारों के मामलों,

कच्चे के आधार पर बटवारों के मामलों, सुखाधिकार से संबंधित मामलों, विक्रय पत्र, दान पत्र वसियतनामा के आधार पर नामांतरण के मामलों का निपटारा सरल तरीके से किया जा सकता है। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों, धारा 138, पराक्रम्य लिखित

अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण का निराकरण किया जाना है। पूर्व के नेशनल लोक अदालत के भांति इस बार भी अधिक से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया जाना है, जिसके संबंध में अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बैठक में चर्चा की गई।

तुंहर विधायक, तुंहर द्वार अभियान का आगाज

संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर ने बिरकोनी में लगाई चौपाल

जोहार छत्तीसगढ़- महासमुंद।
संसदीय सचिव व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर की अगुवाई में ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए तुंहर विधायक तुंहर द्वार अभियान का आगाज हुआ। आज गुरुवार को ग्राम बिरकोनी में संसदीय सचिव चंद्राकर ने सघन जनसंपर्क किया।



ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। संसदीय सचिव चंद्राकर के ग्राम बिरकोनी पहुंचने पर सरपंच का भ्रमण किया। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं बताते हुए मांग रखी। सतनाम पारा के

भुराम कुरेंए राजेश्वर पुनेश्वर कुरें आदि ने पेयजल की समस्या से अवगत कराते हुए बताया कि मुहल्ले के पास में ही तीन एचपी का मोटर चलता है जिसे पाइपलाइन के माध्यम से पानी की आपूर्ति कराई जाए।
साथ ही गली में सीसी रोड पर प्राथमिक शाला में आहाता निर्माण, परसवानी रोड से होते हुए आंगनबाड़ी तक मार्ग निर्माण, सोलर लाइट लगाने व तालाब में पचरी निर्माण की मांग रखी। जिस पर संसदीय सचिव चंद्राकर ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। बाद इसके संसदीय सचिव चंद्राकर ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने शासन की योजनाओं का जिक्र करते हुए

एक नजर

विप कॉलेज द्वारा सामाजिक सहभागिता के अंतर्गत नेवनारा में योगाभ्यास का आयोजन जोहार छत्तीसगढ़-बेमेतरा।

छत्तीसगढ़ युवा विकास संगठन संचालित विप कला, वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय द्वारा 8 जुलाई को प्रातः 9 बजे पूज्य ब्रह्मचारी ज्योतिर्मयानन्द महाराज प्रमुख, सपाद लक्ष्मणधाम आश्रम सलधाद के सानिध्य में एवं ज्ञानेश शर्मा अध्यक्ष योग आयोग छत्तीसगढ़, के मुख्य आतिथ्य में सामाजिक सहभागिता के अंतर्गत चंडी आश्रम नेवनारा में स्वस्थ जीवन के लिए योग थीम पर योग अभ्यास का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता किसान नेता योगेश तिवारी करेंगे। उपरोक्त जानकारी देते हुए प्राचार्य डॉ. मधेश तिवारी ने बताया कि जागरूकता के लिए योग अभ्यास में महाविद्यालय के छात्र सहित ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक शामिल होंगे।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

अंतर्गत प्रचार रथ खाना

जोहार छत्तीसगढ़-बेमेतरा।



प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2022 में अधिसूचित फसल धान सिंचित, धान अंसिंचित, सोयाबीन फसल हेतु अधिक से अधिक किसानों को बीमा योजना में शामिल कराने हेतु रथ के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है जिसके तहत कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नवागढ़ से बीमा रथ सहायक संचालक कृषि आर के शर्मा एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नवागढ़ आर के चतुर्वेदी साथ ही विभागीय अधिकारियों को उपस्थित में विकासखंड नवागढ़ के प्रत्येक ग्राम में प्रचार-प्रसार हेतु रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

छिपली पंचायत के दो वार्ड पंच बर्खास्त

नगरी। ग्राम पंचायत छिपली विकासखंड नगरी के 2 वार्ड पंच वार्ड क्रमांक 14 के संतानू कोषरे एवं वार्ड क्रमांक 15 के टिकेश नवरंग को पंचायत राज अधिनियम के तहत अनुविभागीय दंडाधिकारी के न्यायालय ने वार्ड पंच के पद से पृथक किया है एवं 6 साल के लिए किसी भी पंचायत से चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।

जल गुणवत्ता पखवाड़ा में वलोरीन युक्त शुद्ध पेयजल उपयोग के प्रति किया जा रहा जागरूक

पोलमपल्ली में स्कूली छात्राओं एवं महिलाओं ने निकाली जागरूकता रैली

जोहार छत्तीसगढ़- सुकमा।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत विकासखंड कोटा के ग्राम पंचायत-पोलमपल्ली में जल गुणवत्ता पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम में महिला स्व सहायता समूह, ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव, शिक्षक, मांझी एवं जल जीवन मिशन के क्षमता संबंधित प्रशिक्षण समन्वयक अरुण सरकार सूचना शिक्षा एवं संचार समन्वयक अजीत पोटाई, आईएस, समन्वयक सामदेव उडेंडी एवं आईएस टीम के सदस्य



उपस्थित रहे। जिसमें वर्षा ऋतु के दौरान पेयजल स्रोतों के प्रदूषण के कारण जल जनित बीमारियों जैसे डायरिया, टाइफाइड एवं हैजा आदि से बचाव हेतु समस्त जल स्रोतों का क्लोरीनेशन कर शुद्धिकरण करने हेतु जन जागरूकता लाई जा रही है। ग्राम वासियों के घरों, शालाओं एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में क्लोरीन युक्त

पिथौरा में कलेक्टर ने ली सरकारी काम काज की खबर

जोहार छत्तीसगढ़- पिथौरा।

महासमुंद जिले के कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर आज पिथौरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित आत्मानंद स्कूल, बिहान योजना से संचालित हो रहे स्व सहायता के आजिवका मिशन केन्द्र का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने मातृत्व शिशु अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ अस्पताल के भवन का भी निरीक्षण किया। ज्ञात हो कि महासमुंद कलेक्टर द्वारा अस्पताल का निरीक्षण कर कमियां को तत्काल पूरा करने स्वास्थ्य



अधिकारियों को निर्देशित किया। मातृ शिशु अस्पताल के शुरू होने के बाद से मरीजों को व क्षेत्र वासियों को 15 दिवस के भीतर जल्द ही मातृ शिशु अस्पताल में मरीजों को पूर्ण सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। महासमुंद कलेक्टर ने नगर पंचायत के अधिकारियों के साथ नए गोठान बनाने के लिए खेल मैदान के पीछे

आवश्यकता है

	पद
1. समाचार रिपोर्टर	- 3
2. कम्प्यूटर आपरेटर	- 1
3. ऑफिस कार्य के लिए	- 3

वेतन योग्यतानुसार

इच्छुक युवक/युवति अपना बायोडाटा के साथ संपर्क करें।

दैनिक जोहार छत्तीसगढ़

कार्यालय धरमजयगढ़

मो, 9479177711, 7489419194, 7879121221

पंचायत सचिव स्थापना दिवस

जोहार छत्तीसगढ़- सुकमा।

छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के बैठक 29 जून 22 में पारित निर्णय के अनुसार प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 7 जुलाई को सचिव स्थापना दिवस जिला मुख्यालय में मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में हरीश कवासी, अध्यक्ष, जिला पंचायत सुकमा उपस्थित रहे और विशिष्ट अतिथि के रूप में रामा सोही, जिला पंचायत सदस्य, मांडे बारसे, जिला पंचायत सदस्य, आयती कलमू, अध्यक्ष ज पं सुकमा, डमरू नाग उपाध्यक्ष ज पं सुकमा, नाजीर खान उपाध्यक्ष ज पं छिंदवाड़ा, राजू साहू, अध्यक्ष नगर पालिका सुकमा, उपसंचालक, पंचायत टीएस पैकर, परियोजना अधिकारी बीएस भगत, सहायक परियोजना अधिकारी बलवंत मार्को, नारद मांझी, सीईओ



सुकमा, कैलाश करण सीईओ कोटा उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान पंचायत सचिवों ने शासकीयकरण का मांग का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को सौंपा।
हरीश कवासी ने अपने संबोधन में कहा कि पंचायत सचिव, पंचायत राज व्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करते हैं और ऐसे

सुकमा पुलिस ने बरामद किए 55 लोगों के मोबाईल

जोहार छत्तीसगढ़-सुकमा।



सुकमा साइबर सेल प्रभारी संजय यादव एवं उनके टीम के सहकारी कार्यप्रणाली के चलते 55 गुप्त हुए मोबाईल बरामद किए गये। सुकमा एसपी सुनील शर्मा एवं एसपी किरण चव्हाण एसपी ओम चंदेल के द्वारा मोबाईल मालिकों को सौंपा गया मोबाईल। इस दौरान डीएसपी परमेश्वर तिलकवार, डीएसपी गिरिजाशंकर साव, डीएसपी रजत नाग, डीएसपी पारुल खंडेलवाल, डीएसपी उत्तम सिंह, डीएसपी अभिनव एका, डीएसपी अमित देवांगन, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह, निरमोद सोना, साइबर सेल के मीना गावडे, दिवाकर, लिलाराम पटेल, महेश धुव रहे मौजूद।

नगर पंचायत सीतापुर ने की 5 दुकानों की नीलामी

जोहार छत्तीसगढ़-सीतापुर।



सीतापुर नगर पंचायत द्वारा पूर्व में नीलामी की गई पांच दुकानों की राशि प्राप्त न होने के कारण उसको राजसात करते हुए आज सीतापुर में पुनः उन दुकानों की नीलामी का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि आज सीतापुर नगर पंचायत में, दुकानों की नीलामी का आयोजन किया गया था, जिसमें 3 दुकाने न्यू बस स्टैंड सीतापुर की और दो दुकाने आरईएस कॉलोनी की हैं, इस नीलामी में सीतापुर के काफी लोग एकत्रित हुए और बड़ चढ़कर बोली लगाई, आपको बता दें कि 5 दुकानों की नीलामी में नगर पंचायत को 54 लाख 13 हजार रुपए प्राप्त हुए, दुकान की नीलामी के लिए सीतापुर तहसीलदार शशिकांत दुबे, नगर पंचायत सीएमओ सुशील तिवारी, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रेमदान कुजुर, और सीतापुर के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में हुआ।

पंजाब के अकाल यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम अचानक पहुंची नानक सागर

प्रमाण मिला गुरुनानक देव जी पहुंचे थे यहां

जोहार छत्तीसगढ़- महासमुंद।

जिले के प्रसिद्ध हो चुके नानक सागर में श्री गुरुनानक देव जी के आगमन की खबरों के प्रकाशन के बाद सोमवार को पंजाब के तलवंडी साहिब स्थित अकाल यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर रिसर्च टीम के साथ नानक सागर पहुंचे। अपने रिसर्च के पहले चरण में ही उन्होंने श्री गुरुनानक देव जी के यहां आगमन के प्रमाण मिलने की बात कही है। सोमवार को नानक सागर में अचानक तलवंडी साहिब की अकाल यूनिवर्सिटी के सहायक प्राध्यापक गुरनाम सिंह पहुंचे। उन्होंने नानक सागर से लगे गढ़फ लखर स्थित गुरुद्वारा देखने के बाद अपने सहयोगी गुरविंदर सिंह दिक्षी वाले, जसपाल सिंह खेरा एवं सतबीर सिंह के साथ गुरु के नाम की जमीन देख कर समीप के ग्राम जेवरा में एक मात्र शिखर



परिवार के गुरुद्वारा पहुंचे। इसके बाद ग्रामीणों एवम गढ़फु लखर गुरुद्वारा कमेटी वालों से चर्चा कर कोई 100 साल पुराना मिसल रिकॉर्ड का अवलोकन किया। इन सब के अवलोकन के बाद प्रथम दृष्टि में श्री गुरुनानक देव जी के यहां रुकने की पुष्टि हुई है।
उदासी यात्राओं में छः ग का उल्लेख नहीं
गुरनाम सिंह ने इस प्रतिनिधि द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया कि श्री गुरुनानक देव जी की पहली उदासी यात्रा में अमरकंटक से पूरी जाने का उल्लेख ग्रन्थों में दर्ज है परन्तु छत्तीसगढ़ में रुकने का उल्लेख नहीं है। ओडिसा के कटक, पूरी एवं भद्रक तक रुकने की जानकारी दी जाती है। इस बीच किस रास्ते से गुरु जी की यात्रा हुई थी इसका उल्लेख नहीं है। इस पर लगातार रिसर्च भी किये जा रहे हैं। वे स्वयं इस रिसर्च हेतु कालाहाण्डी ओडिसा जा रहे थे। इसके लिए वे हरिश्चंकर रोड पहुंचे थे। वहां की सिक्ख संगत ने उन्हें बताया कि गढ़फुलखर में भी गुरु साहेब रुके थे। उनसे थोड़ी जानकारी मिलते ही उन्होंने कालाहाण्डी जाने की बजाय छत्तीसगढ़ का रुख कर सीधे बसना पहुंचे और बसना से गढ़फु लखर पहुंच गया। गढ़फु लखर गुरुद्वारा में में इनकी मुलाकात स्थानीय निवासी जसपाल सिंह से हुई। जसपाल सिंह ने इन्हें नानक सागर एवं जेवरा ले जाकर वहां के अत्यधिक वृद्धों से मिलकर बातचीत की। इस बातचीत में उन्हें ग्रामीणों ने कोई 100 साल पुराना मिसल रिकॉर्ड भी दिखा दिया जिसमें कोई 5 एकड़ कृषि भूमि श्री गुरुनानक देव जी के

नाम है। इस रिकॉर्ड की सच्चाई परखने के बाद गुरु के यहां रुकने की बात निश्चित हो गयी।
जेवरा में बंजारा समाज बना रहा गुरु का मंदिर
इधर गुरनाम सिंह ने जेवरा जाकर वहां भी एक ही सिक्ख परिवार द्वारा बनाये गए गुरुद्वारा के साथ बंजारा समाज द्वारा श्री गुरुनानक देव जी के बन रहे विशाल मंदिर को भी देखा। इन सबके अवलोकन से पता चला कि छ ग में गुरुनानक देव जी के मानने वालों में बंजारा समाज भी सिक्खों के बराबर चल रहा है।
गुरु की निशानियों को आधुनिक बनाने से बचना चाहिए
तलवंडी पंजाब से आये प्रोफेसर गुरनाम सिंह ने वर्तमान में गुरु घर गुरुद्वारा बनवाने वालों से गुरु के बैठने के चबूतरे का आधुनिकीकरण नहीं किये जाने की बात कहते हुए उसी चबूतरे को बतौर निशानी रखने की बात कही। उन्होंने यहां काम कर रहे सिक्खों से अपील की है कि गुरु की किसी भी निशानी का आधुनिकीकरण नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उनके संरक्षण की आवश्यकता है।
पंजाब से रिसर्च में आये गुरनाम सिंह ने रायपुर निवासी रिंकू ओबेरॉय द्वारा नानक सागर में गुरु के चरण पड़ने के मामले में गहन रिसर्च कर अनेक प्रमाण जुटाए हैं। इसके लिए हमें रिंकू ओबेरॉय की मुक्त कंठ से प्रशंसा की जानी चाहिए।